जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 51 संख्याः 65 प्रभात कोटा, गुरूवार 18 दिसम्बर, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'अरे दीवाने ऐसा काम न कर, राम का नाम बदनाम न कर'

शशि थरुर का लोकसभा में यह व्यंगात्मक भाषण इस बात का संकेत है कि राहुल की सोच बदल रही है, बगावती से तेवर दिखाने वाले पार्टी के नेताओं के प्रति

- पहले राहुल की सोच होती थी, अगर पार्टी के कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं तो पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं।
- पर, अब पार्टी द्वारा शशि थरुर को लोकसभा में खुलकर बोलने का मौका देना, इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी का रुख ''बगावती'' तेवर वाले नेताओं के प्रति कुछ नरम हुआ है।
- दूसरी ओर शशि थरुर भी कुछ सध कर बोल रहे हैं, भाजपा व प्र.मंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांधते समय।
- शशि थरुर ने यह महसूस किया कि धीरे-धीरे भाजपा उनके चुनाव क्षेत्र, तिरुअनंतपुरम् में उनके वोट बैंक में सेंध मार रही है और यह थरुर के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी।
- यह ही मनीष तिवाड़ी के बारे में हुआ। मनीष को लग रहा था कि पार्टी में उनको वह स्थान नहीं मिल रहा, जिसका वे अपने आपको हकदार मानते थे। पर, जब पार्टी ने उन्हें एसआईआर पर राज्यसभा में प्रथम वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और बहुत सराहा गया और कांग्रेस के लिए यह सुखद ''डवलपमैंट'' था।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। शशि थरूर ने सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी नाम हटाने के निर्णय पर विरोध जताया। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए न्यूक्लियर बिल पर भी अपनी बात रखी।

मनीष तिवारी का एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट) पर भाषण सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद प्रभावपूर्ण हमला था, जिसमें उन्होंने सरकार की गलतियों को उजागर किया और सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शशि थरूर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनन्तपुरम में भाजपा के प्रवेश करने से थरुर को झटका लगा है और वे थोड़े शांत पड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, थरूर की समस्या के पीछे के.सी. वेणुगोपाल हैं, जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

इस परिदृश्य में पार्टी के भीतर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर शशि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सबका बीमा सबकी रक्षा' बिल पारित

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान करने वाले सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी।

राज्यसभा ने विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद आज विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार 16 दिसंबर को ही पारित कर चुकी थी।

इस विधेयक का उद्देश्य बीमा संबंधी तीन कानूनों में संशोधन करना है। इसमें बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के अलावा कारोबार को आसान बनाने के लिए और भी कई उपाय किये गये हैं।

- राज्यसभा ने आज इसे स्वीकृति प्रदान की, लोकसभा में 16 दिसम्बर को यह बिल पारित हो चुका है।

पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि एक बीमा कंपनी का गैर-बीमा कंपनी के साथ विलय किया जा सकता है या उसे बीमा तथा गैर-बीमा कंपनियों में बांटा जा सकता है। इसके लिए बीमा नियामक से अनुमति लेनी होगी। अब पांच प्रतिशत से कम के हिस्सेदारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारत का औद्योगिक उत्पादन घट रहा है'

राहुल गांधी जर्मनी की पाँच दिवसीय यात्रा के दौरान बी.एम.डब्ल्यु. वर्ल्ड की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे

- अवलोकन के दौरान, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत का औद्योगिक उत्पादन घटना दुख का विषय है, क्योंकि किसी भी देश की सफलता की कुँजी उसका औद्योगिक उत्पादन होता है।
- राहुल गांधी की जर्मनी की इस यात्रा की घोषणा लोकसभा के सत्र के दौरान की गई थी तथा इस घोषणा पर भाजपा ने कटाक्ष किया था कि राहुल गांधी के बार-बार विदेश यात्रा पर जाने से, राहुल गांधी के अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रति समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। जर्मनी के म्यूनिख शहर में प्रसिद्ध बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड का गाइडेड टूर करते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि किसी भी देश की सफलता के लिए उत्पादन सबसे अहम है, जबकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र गिरावट के दौर से गुजर रहा है।

समग्र आर्थिक विकास में मैन्युफैक्चरिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि यहां भारतीय झंडा लहरा रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शोरूम का दौरा करते, वहां मौजूद लग्ज़री कारों को नजदीक से देखते और बी.एम.डब्ल्यू. वर्ल्ड घूमने आए लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वहां 450 सीसी की एक बाइक भी है।

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा, ''भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। किसी भी देश की सफलता की कुंजी उत्पादन होता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है, जबकि वास्तव में इसे बढ़ना चाहिए।''

एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, ''मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग गिरावट में है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा उत्पादन करने की ज़रुरत है, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करने की ज़रुरत है।''

राहुल गांधी दुनिया भर की 117 प्रगतिशील पार्टियों के एक प्रमुख समूह, ''प्रोग्रेसिव अलायंस'' के निमंत्रण पर जर्मनी के दौरे पर हैं।

अपने दौरे के दौरान, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जर्मनी के अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान, वे बुधवार को होने वाले एक बड़े आईओसी (इण्डियन ओवरसीज़ कांग्रेस) कार्यक्रम में शामिल होंगे और यूरोप भर के आईओसी नेताओं से मुलाकात करेंगे।

यह कार्यक्रम कांग्रेस की वैश्विक पहुंच और गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आईओसी के अनुसार, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से जुड़ने के लिए वहां हैं। इस दौरान एनआरआई से जुड़े मुद्दों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एच वन बी वीज़ा की फीस का सर्वाधिक असर टाटा और इंफोसिस पर पड़ेगा

अब इन कंपनियों को भारतीयों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए एक लाख डॉलर की वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी

- ट्रंप के, एच वन बी वीज़ा शुल्क को एक लाख डॉलर करने के फैसले को आउट सोर्सिंग और स्टाफिंग इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा हैं। यह उद्योग एच वन बी वर्कस तलाश करने वाली कंपनियों के लिए बिचौलिए का काम करता है। इनमें टाटा कंसलटैंसी, इंफोसिस व कॉग्निज़ैंट शामिल हैं।
- अमेरिका के औद्योगिक विशेषज्ञों का मत है कि भले ही शुल्क वृद्धि को कानून की मदद से रोक दिया जाए, पर, इससे अमेरिकन वीज़ा की मांग में भारी कमी आएगी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। अमेरिका के बाहर से नियुक्त किए जाने वाले नए एच-1बी कर्मचारियों पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 1,00,000 डॉलर का शुल्क तय किए जाने से आईटी आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह उद्योग लंबे समय से दोनों राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा है।

यह शुल्क ट्रंप प्रशासन द्वारा अब तक कुशल विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगाई गई सबसे बड़ी पाबंदी है।

इसका असमान रूप से ज्यादा असर उन बहुराष्ट्रीय स्टाफिंग कंपनियों पर पड़ेगा, जो एच-1बी कर्मचारियों की तलाश कर रहीं कंपनियों के लिए बिचौलिये की भूमिका निभाती हैं। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड और कॉग्निज़ैंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस कॉर्प शामिल हैं।

मई 2020 से मई 2024 के बीच टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस और कॉग्निज़ैंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस में की गईं लगभग 90 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों से मंज़ूरी मिली थी।

ब्लूमबर्ग के विश्लेषण के अनुसार, इसी अवधि में इंफोसिस की 93 प्रतिशत से अधिक नई एच-1बी नियुक्तियों, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले भागवत

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति एनक्लेव में मुलाकात की। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से की गई।

- उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के अधिकारिक एक्स हैंडल से इस मुलाकात की जानकारी दी गई और बताया गया कि सरसंघ चालक भागवत ने उनसे सांस्कृतिक व शैक्षिक मसलों पर चर्चा की।

सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति और सरसंघ चालक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) को भारत से अलग करने में मदद देंगे'

बाँग्लादेश के एक नेता के इस बयान पर नाराज़ केन्द्र सरकार ने बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

- बाँग्लादेश की नैशनल सिटिज़न पार्टी के एक नेता ने धमकी दी है कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और ''सैवन सिस्टर्स'' अर्थात् सात पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने में मदद करेगा।
- भारत में बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर उन्हें बाँग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाँग्लादेश के नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणी पर भारत सरकार की नाराज़गी से अवगत कराया गया।

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। ढाका में भारतीय उच्चायोग को दी गई धमकियों और बाँग्लादेशी राजनीतिक नेताओं के भारत विरोधी भड़काऊ बयानों पर औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज करने के लिए, भारत ने दिल्ली में मौजूद बाँग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया है।

यह सम्मन बाँग्लादेश की नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के एक नेता द्वारा दी गई उस धमकी के बाद भेजा गया है, जिसमें कहा गया था कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और ''सेवन सिस्टर्स'', जो कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, को भारत से अलग करने में मदद करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमीदुल्लाह को बाँग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, उनका बयान, ''विशेष रूप से, उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर खींचा गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आस-पास ''सुरक्षा के लिए खतरा'' पैदा करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है।

भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह बाँग्लादेश में हाल की घटनाओं के संदर्भ में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाए गए झूठे कथानक को पूरी तरह से नकारता है।

मंत्रालय ने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो मामले की पूरी जांच की है और न इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रमाण साझा किए हैं।''

बयान में कहा गया, ''भारत के बाँग्लादेश के लोगों के साथ गहरे और दोस्ताना रिश्ते हैं, जिनकी जड़ें मुक्ति संग्राम में निहित हैं और ये रिश्ते विभिन्न विकासात्मक तथा दोनों देशों की जनता की पहल से मजबूत हुए हैं। हम बाँग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं और हमने लगातार स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों की अपील की है, जो शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत, बाँग्लादेश में मिशनों और पोस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।''

''सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करे देंगे'', छात्रों की पार्टी नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख हसनात अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की। उन्होंने इंकलाब मंच द्वारा आयोजित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारी ''वर्क फ्रॉम होम'' करेंगे

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिये गुरुवार (18 दिसंबर) से 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देश जारी किये।

- दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा 18 दिसम्बर से यह आदेश सभी सरकारी व निजी संस्थानों पर लागू होगा।

मिश्रा ने कहा कि ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित, ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। दिशा-निर्देशों में यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ नैशनल हैरल्ड मुकदमे से पीछे हटने को तैयार नहीं है भाजपा

भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय ने तकनीकी कारणों के आधार पर ई.डी. को मनी लॉण्डरिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ जाँच की कार्यवाही पर रोक लगाई है

- प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि न्यायालय का निर्णय, राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई व गुणवत्ता में कमी के कारण नहीं लिया गया है।
- अतः, यह कहना पूर्ण सच नहीं है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को ''रिलीफ'' (रियायत) मिली है, न्यायालय से।
- दूसरी ओर, कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से मीडियाकर्मियों के समक्ष कहा कि न्यायालय का निर्णय, प्र.मंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के मुँह पर चपत है तथा दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। सत्तारूढ़ भाजपा को न्यायपालिका से भी नकारात्मक निर्णय स्वीकार करने की आदत नहीं, इसलिए वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे नेशनल हैरल्ड मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है।

सरकारी सूत्रों ने बताया, असल में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) को कोर्ट के आदेश पर स्टे मिलने की संभावना है और उसे नेशनल हैरल्ड की जब्त की गई करोड़ों की संपत्ति को वापस नहीं करना पड़ेगा।

भाजपा के नेताओं ने, नाम न बताने की शर्त पर, कहा कि हमें इस मामले को लगातार आगे बढ़ाना होगा और हर कानूनी विकल्प का पता लगाना होगा, क्योंकि यह मामला हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, और वह है गांधी परिवार को दबाव में रखना।

दिल्ली की एक अदालत ने एक दिन पहले ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था, और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा-नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख तेज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ''मुंह पर तमाचा'' करार दिया।

खड़गे ने मीडिया से कहा, ''यह मामला एक राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था। इसे गांधी परिवार को परेशान करने के लिए तैयार किया गया था। इस निर्णय के बाद मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह उनके मुंह पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है।''

भाजपा ने इसके जवाब में अपनी हमलावर रणनीति को तेज किया, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर ''राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार होने'' का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, और उन्होंने कांग्रेस के ''राजनीतिक प्रतिशोध'' के दावों को खारिज किया।

भाटिया ने खड़गे पर आरोप लगाया कि ''वे अदालत के निर्णय को क्लीन चिट के रूप में प्रस्तुत करके जनता को गुमराह कर रहे हैं,'' और यह तर्क दिया कि यह आदेश कानूनी और तकनीकी आधार पर था, न कि आरोपों की सच्चाई पर। उन्होंने कहा, ''अगर कोई राजनीति में सबसे भ्रष्ट है, तो वह गांधी परिवार है,'' अदालतों में कई बार जाने के बावजूद गांधी परिवार को कोई कानूनी राहत नहीं मिली।

भाजपा नेता के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही बिना पंजीकृत एफआईआर के नहीं चल सकती, लेकिन इस आधार पर अन्य एजेंसियों को अपनी जांच जारी रखनी थी।

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हैरल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट की संज्ञान लेने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि पीएमएलए की कार्यवाही इस आधार पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह मामला सुब्रमण्यम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओमान के सुल्तान ने हवाई अड्डे पर किया मोदी का स्वागत

मस्कट, 17 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की चार दिन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में बुधवार शाम यहां मस्कट पहुंच गए, जहां हवाई अड्डे

- प्र.मंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे।

पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।

मोदी ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। उनके स्वागत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई।

प्रधानमंत्री ने मस्कट पहुंचते ही ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ बैठक की।